International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 05-09-2019; Accepted: 06-10-2019
www.educationjournal.in
Volume 4; Issue 6; November 2019; Page No. 28-32

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वर्तमान स्थिति

प्रशान्त कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश
बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के विकास की बुनियाद कृषि के विकास पर आधारित है। नदियों में जल की प्रचुरता, उर्वर भूमि के अलावा, मेहनती स्वभाव एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य का भाव बिहार के लोगों में भरा हुआ है। अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। इसके विपरीत सीमित संसाधनों के ही आधार पर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि के साथ–साथ उद्योगों का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के विकास में बाधक तकनीकी पिछड़ापन, पूँजी की कमी, अधिसंरचना, सांस्थानिक समस्या, कीमत संबंधी समस्या एवं करारोपण है। सरकार को एक स्वतंत्र नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि उन्नत तकनीकी की सहायता से इन उद्योगों का विकास हो।

मूल शब्द: प्रसंस्करण, बिहार, कृषि, पूँजी की कमी

प्रस्तावना
कृषि उत्पादों और फल–सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। साथ ही प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहल हुई है। किंतु दुखद स्थिति यह है कि भारत में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का मात्र 0.5 से 1.0 प्रतिशत ही परिशोधन हो पाता है कि जो विश्व के अन्य राष्ट्रों के अपेक्षा नगण्य है। ऐसी स्थिति में बिहार की स्थिति शून्य जैसी है। किन्तु परिशोधन पर आधारित उद्योगों की महत्ता को नकारना संभव नहीं है। कृषि उत्पादन से खाद्य पदार्थ तक परिशोधन करने से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। (जैसे चूड़ा, सुजी, नुडल्स, फलों के रस, शिशु खाद्य सामग्री, दुध पाउडर आदि)। इसके अतिरिक्त आवश्यक तेल, ओलेओरेजीन, विटामिन्स, रंग, सुगंधी, कॉर्न फ्लेक्स, सब्जी मसाला, आलू–चिप्स पारम्परिक खाद्य पदार्थ के शीघ्र बनने वाले मिश्रण आदि तैयार करके कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है। अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि खाद्य–प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार केवल प्राथमिक स्तर पर ही पहुँच सका है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के विकास में बाधक तकनीकी पिछड़ापन, पूँजी की कमी, अधिसंरचना, सांस्थानिक समस्या, कीमत संबंधी समस्या एवं करारोपण है। सरकार को एक स्वतंत्र नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि उन्नत तकनीकी की सहायता से इन उद्योगों का विकास हो।

बिहार में कृषि उत्पादों की बहुलता है। अगर ध्यान दिया जाय तो यह प्रदेश कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों का हब बन सकता है। वैसे स्टार्टअप इण्डिया का असर भी बिहार में दिखने लगा है। नई सोच और आइडिया के साथ युवा आ रहे हैं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) ने हाल में ही जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया था, उसमें 125 से अधिक नए आइडिया आए। इनमें कई फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी हैं। राज्य सरकार नई स्टार्टअप नीति भी ला चुकी है। एक ओर जहां एंजेल इन्वेस्टर बिहार के नए आइडिया को सराह रहे हैं और इनमें पूंजी लगाने का मन बना रहे हैं, वहीं सरकार भी ऐसे उद्यमियों को आर्थिक मदद देने के लिए 500 करोड़ रूपये का वेंचर कैपिटल फंड लाई है। इसके तहत नए आइडिया वाले उद्यमियों को 10 लाख रूपये की मदद दी जाएगी।

राज्य सरकार और औद्योगिक संस्थाओं का ध्यान इसी तरह रहा तो आने वाले वर्षों में बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाने में देर नहीं लगेगी। कारण कि यहां के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का पूरी दुनिया में जवाब नहीं है। भागलपुर का जर्दालु आम देश–दुनिया में मशहुर है। यहां के अन्य आम के बगान, लीची और हरे केले भी कम मशहूर नहीं है। साथ ही शायद ही कोई शहर हो, जहां मिथिलांचल क्षेत्र का मखाना नहीं जाता हो। बिहार पहला राज्य है, जो हॉफ बॉयल चावल का उत्पादन गुणवत्ता के साथ कर रहा है और अरब देशों में बिरयानी के लिए इसकी मांग बड़े पैमाने पर की जा रही है। जरूरत बस इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने की है।

बिहार की औद्योगिक संरचना
वर्ष 2012–13 में किए गए सबसे हाल के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 3,347 इकाइयां थी जबकि 2010–11 में उनकी संख्या 2,807 थी। इस प्रकार यह 19.2 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है (तालिका 3.1)। पूरे देश में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम – 8.6 प्रतिशत थी। चालू कारखानों की बात की जाय, तो 2012–13 में बिहार में उनकी संख्या 2,946 थी जो कुल निबंधित कारखानों का 88.1 प्रतिशत है। पूरे देश में संबंधित अनुपात काफी कम – 80.1 प्रतिशत था। कारखानों का कृषि आधारित और गैर–कृषि आधारित कारखानों में बंटवारा दर्शाता है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा राष्ट्रीय आंकड़े (39.5 प्रतिशत) से कम है। इसका वास्तव में यह अर्थ हुआ कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के लिए काफी संभावना मौजूद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है।

तालिका 1: 2014–15 में निबंधित अतिलघु / लघु /मध्यम उद्योगों के उद्यम

प्रमंडल	जिला	अतिलघु	लघु	मध्यम	योग
पटना	पटना	175	50	4	229
	नालंदा	54	0	1	55
	भोजपुर	86	9	7	102
	बक्सर	70	9	0	79
	कैमूर	20	4	1	25
	रोहतास	76	7	1	84
	मुंगेर	32	0	0	32

मुंगेर	जमुई	17	0	0	17
	शेखपुरा	42	0	0	42
	लखीसराय	33	0	1	34
	बेगूसराय	73	15	0	88
	खगड़िया	25	0	0	25
भागलपुर	भागलपुर	25	3	0	28
	बांका	4	0	0	4
पूर्णिया	पूर्णिया	53	2	0	55
	अररिया	25	1	0	26
	किशनगंज	28	1	0	29
	कटिहार	34	2	0	36
मगध	गया	24	1	1	26
	नवादा	31	1	0	32
	औरंगाबाद	13	1	0	14
	जहानाबाद	17	0	0	17
	अरवल	14	0	1	15
दरभंगा	दरभंगा	65	2	0	67
	मधुबनी	40	0	0	40
	समस्तीपुर	34	1	0	35
कोशी	सहरसा	47	0	0	47
	सुपौल	16	0	0	16
	मधेपुरा	89	0	0	89
तिरहुत	मुजफ्फरपुर	173	12	1	186
	वैशाली	115	11	0	126
	पश्चिम चंपारण	25	5	0	30
	सीतामढ़ी	22	1	0	23
	पूर्व चंपारण	77	9	2	88
	शिवहर	27	0	0	27
सारण	गोपालगंज	46	1	0	47
	सीवान	96	1	1	98
	सारण	36	1	1	38
	योग	1979	150	22	2051

स्रोतः उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट

तालिका 2: बिहार में उद्योगों की संरचना (2012–13)

औद्योगिक समूह	कारखानों की संख्या		चालू कारखाने (संख्या)		स्थिर पूंजी (करोड़ रू.)		नियोजित व्यक्ति (संख्या)	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
कृषि आधारित								
खाद्य उत्पाद / पेय /तंबाकू	40592	820 (2.0)	33627	702 (2.1)	164313	3055 (1.9)	2117725	26129 (1.2)
वस्त्र / परिधान	27743	28 (0.1)	19794	25 (0.1)	142912	40 (0)	2331619	3376 (0.1)
चर्म एवं चर्म उत्पाद	4055	7 (0.2)	3027	7 (0.2)	7278	7 (0.1)	285393	915 (0.3)
काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद / फर्नीचर	5660	207 (3.7)	4619	200 (4.3)	11014	36 (0.3)	142254	2721 (1.9)
कागज एवं कागज उत्पाद / मुद्रण तथा अभिलेखित माध्यम का पुनरूत्पादन / प्रकाशन गतिविधियाँ	11307	79 (0.7)	9100	71 (0.8)	60646	184 (0.3)	428041	2134 (0.5)
उप – योग	89357	1141 (1.3)	70173	1005 (1.4)	386163	3322 (0.9)	5305032	35275 (0.7)
गैर–कृषि आधारित								
कोक तथा शोधित पेट्रोलियम उत्पाद	1536	61 (4)	1182	59 (5)	161189	1615 (1)	99774	2455 (2.5)
रसायन / रासायनिक उपाद	11426	43 (0.4)	9167	35 (0.4)	148024	51 (0)	633659	1386 (0.2)
मूल औषधीय उत्पाद	4907	26 (0.5)	4224	26 (0.6)	69263	14 (0)	532015	807 (0.2)
रबर / प्लास्टिक उत्पाद	12677	51 (0.4)	10057	50 (0.5)	60794	46 (0.1)	539155	809 (0.2)
अधातु खनि उत्पाद	25253	1559 (6.2)	21375	1364 (6.4)	201777	403 (0.2)	891917	64872 (7.3)
मशीन और उपकरण से इतर धातु / फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद	28083	156 (0.6)	22843	136 (0.6)	531427	237 (0)	1653629	4543 (7.3)
बिजली के समान / मशीन एवं उपकरण एनईसी / मशीन उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	20346	53 (0.3)	16555	50 (0.3)	113124	454 (0.4)	1205515	1722 (0.1)
मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी–ट्रेलर / अन्य परिवहन उपकरण	7957	10 (0.1)	6761	10 (0.1)	167712	8 (0)	1058498	693 (0.1)
अन्य (32 अन्य विनिर्माण सहित)	13207	247 (1.9)	10938	211 (1.9)	311532	316.14 (10.1)	685687	3787 (0.6)
उप –योग	125392	2206 (1.8)	103102	1941 (1.9)	1764841	3144.56 (0.2)	7299849	81124 (1.2)
कुल योग	214749	3347 (1.6)	173275	2946 (1.7)	2151003	6466.37 (0.3)	12604881	116399 (0.9)

स्रोतः वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2012–13

बिहार में कारखानों का औसत आकार राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा छोटा है। वर्ष 2012–13 में भारत में कारखानों की कुल संख्या में बिहार का हिस्सा 15. 1 प्रतिशत था लेकिन अन्य सभी विशेषताओं में इनका हिस्सा काफी कम था – स्थिर पूंजी 0.30 प्रतिशत, कार्यशील पूंजी 0.41 प्रतिशत, नियोजित व्यक्तियों की संख्या 0.90 प्रतिशत, निर्गत मूल्य 0.86 प्रतिशत और निवल मूल्यवर्धन 0.15 प्रतिशत। हालांकि छोटे कारखानों की बहुलता प्रत्याशित परिघटना है क्योंकि बिहार में औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी भी नवजात स्थिति में है। बिहार में कारखानों की संख्या राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा तेज

गति से बढ़ रही है। इसलिए आशा की जा सकती है कि राज्य में लगने वाले कुछ भावी कारखाने बड़े कारखाने होंगे जिससे औद्योगिक क्षेत्र अधिक जीवंत हो जाएगा।

किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास से उत्पादकता ही नहीं बढ़ती है, उससे कामगारों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं जो पहले निम्न उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं। भारतीय औद्योगिक सर्वेक्षण के तहत शामिल कारखानों में रोजगार का परिणाम के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2012–13 में बिहार में ऐसे कारखानों में 1.16 लाख कामगार कार्यरत थे जो पूरे देश में नियोजित 129.50 लाख व्यक्तियों के 1 प्रतिशत से भी कम हैं। यह भी बिहार के कारखानों के अपेक्षाकृत छोटे आकार का परिणाम है। अगर किसी कामगार के वेतन के स्तर की बात करें, तो बिहार में यह प्रति वर्ष मात्र 90.8 हजार रू. था जो पूरे देश के लिए 184.9 हजार रू. का महज आधा ही है।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

बिहार में काफी व्यापक जैव–विविधता है और यहां के खेतों में खाद्यानों के अलावा भी अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में तिलहन, रेशेदार फसलें, फल, सब्जियां, ईख और चाय शामिल हैं। इनके अतिरिक्त दूध का भी बिहार में अच्छा–खासा उत्पादन होता है। इस प्रकार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के लिए भारी अवसर मौजूद हैं।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थिति तालिका 3 में प्रस्तुत है। मार्च 2014–15 के अंत में राज्य में 366 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग थे जिनमें से 207 (55.4 प्रतिशत) चालू थे। हालांकि अनाज (चावल, गेहूं और मक्का) आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन अनेक दुग्ध उत्पाद और खाद्य तेल उत्पादक इकाइयां भी हैं। इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 45 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

तालिका 3: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की उपलब्धियां

सितंबर 2015 तक					
परियोजना	इकाइयों की संख्या		वित्तीय प्रगति (लाख रू.)		रोजगार (संख्या)
	कुल	व्यावसायिक उत्पादन वाली	स्वीकृत परियोजना व्यय	प्रगति के अनुरूप विमुक्त अनुदान	
चावल मिल	169	89	156409.60	12963.62	5745
गेहूं मिल	44	30	35060.15	4729.87	104
मक्का प्रसंस्करण	37	21	51053.51	3994.33	2281
ग्रामीण कृषि व्यापार केन्द्र	52	24	46468.78	6644.26	1572
फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	16	7	10819.25	1297.89	168
दूध प्रसंस्करण	11	6	24241.58	1082.61	598
मखाना प्रसंस्करण	3	2	369.63	64.82	56
शहद प्रसंस्करण	2	2	224.14	69.80	32
बिस्कूट निर्माण	9	8	20875.95	2655.10	1906
खाद्य तेल निर्माण	10	8	50749.62	3174.67	2001
अन्य परियोजनाएं	24	13	28647.49	2105.38	1900
फूड पार्क	2	0	30980.40	150.00	28597
योग	379	210	445900.10	28932.35	44960
2014–15					
परियोजना	इकाइयों की संख्या		वित्तीय प्रगति (लाख रू.)		रोजगार (संख्या)
	कुल	व्यावसायिक उत्पादन वाली	स्वीकृत परियोजना व्यय	प्रगति के अनुरूप विमुक्त अनुदान	
चावल मिल	162	89	153990.91	9995.15	5566
गेहूं मिल	42	27	34740.94	3365.34	16
मक्का प्रसंस्करण	34	21	40079.50	2509.78	2200
ग्रामीण कृषि व्यापार केन्द्र	52	24	44468.78	5031.60	1562
शीत गृह	3	1	1510.12	0.00	1834
फल एवं सब्जी प्रंसंस्करण	14	7	10445.91	1102.03	122
दूध प्रसंस्करण	10	5	13441.58	1063.92	553
मखाना प्रसंस्करण	3	2	369.63	64.82	56
शहद प्रसंस्करण	2	2	224.14	69.80	32
बिस्कूट निर्माण	9	7	20875.95	2480.46	1906
खाद्य तेल निर्माण	10	8	50749.62	2874.66	2001
आइस्क्रीम	4	2	1073.38	184.37	89
अन्य परियोजनाएं	19	12	24420.21	1770.76	1400
फूड पार्क	2	0	30980.40	150.00	28597
योग	366	207	429371.07	30662.69	45934

स्रोतः खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट

वित्तीय वर्ष 2016–17 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, 1 सितम्बर 2016 से लागू की गई है, जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक इकाइयों को विशेष सुविधायें दने का प्रावधान है।
- सिंगल विंडो सिस्टम के सरल, सुदृढ़ एवं कारगर बनाने तथा राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, 2006 को निरसित कर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 को 01 सितंबर 2016 से लागू की गयी है।
- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से स्विकृति हेतु ऑन लाईन फाइलिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों से कॉमन एप्लीकेशन फार्म में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् को निर्णय लेने का प्रावधान है।
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली – 2016 अधिसूचित किया गया

है।

- राज्य के समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट–अप परिस्थिति तैयार हो, जिससे युवाओं का सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में बिहार उभरे तथा जहाँ सभी संभावित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ढ़ाँचे का विकास हो सके इसी मद्देनजर बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016 दिनांक 07सितंबर, 2016 से लागू की गयी है।
- मेंम वि क्वपदह ठनेपदमे के तहत राज्य सरकार द्वारा मेंम वि क्वपदह ठनेपदमे त्मवितउे को लागू करने हेतु विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा – श्रम, वाणिज्यकर, पर्यावरण के क्षेत्र में अनेकों सुधार लाया गया है। इसके तहत उद्योग संवाद पोर्टल (ूनकलवहण्इपींतण्हवअण्पद) के माध्यम से राज्य के सभी विभागों द्वारा प्रकाशित अधिनियमों / नियमों / नीतियों / परिपत्रों / सूचनाओं / अधिसूचनाओं की जानकारी दी जाती है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा मेंम वि क्वपदह ठनेपदमे से संबंधित बिन्दुओं का प्रतिउत्तर रैंकिंग वर्ष 2015–16 में जो 16.41 प्रतिशत था वह वर्ष 2016–17 में बढ़कर 75.86 प्रतिशत हो गया।
- उद्योग संवाद पोर्टल (ूनकलवहण्इपींतण्हवअण्पद) पर कार्यरत उद्यमियों द्वारा किये गये व्दसपदम 234 फनमतपमे एवं नये उद्यमियों द्वारा व्दसपदम 394 फनमतपमे का ऑन लाईन जवाब दिया गया साथ ही इसी पोर्टल एवं समाचार–पत्रों के माध्यम उद्यमी बनने हेतु इच्छुक कुल 1,753 आवेदकाके को उद्योग लगाने हेतु मार्ग–दर्शन / मेंटरिंग का कार्या उद्योग मित्र द्वारा किया गया ।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्सान अधिनियम, 2016 लागू होने के पश्चात् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा कुल 171 नए प्रस्तावों पर स्वीकृति (स्टेज –1 ब्समंतंदबम) प्रदान की गयी जिसमें प्रस्तावित निवेश 2,165.00 करोड़ रू. है।
- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा वर्ष 2006 से 2016 (दिनांक 30.06. 2016 तक) कुल 2,345 प्रस्तावों पर स्वीकृति।
  - रू. 2,19,444.00 करोड़ की पूँजी निवेश प्रस्तावित।
  - कुल 314 परियोजनाएँ स्थापित।
  - रू. 8632.56 करोड़ का पूँजी निवेश।
  - 15,568 व्यक्ति नियोजित।
  - 178 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर।

- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत निम्नांकित रियायतें / सुविधाओं के लिए राशि प्रतिपूर्ति की गयी हैः
  - 77 इकाइयों को रू. 18.52 करोड़ कैपटिव पावर / डी. जी. सेट अनुदान वितरित।
  - वैट की प्रतिपूर्ति हेतु 235.53 करोड़ रू. की राशि वाणिज्य कर विभाग को आवंटित।
  - ए.एम.जी. / एम.एम.जी. के अन्तर्गत छूट प्रदान करने हेतु रू. 89.50 करोड़ बिहार पावर (होल्डिंग) कम्पनी को भुगतान किया गया।
- खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पी. ए. एम. सी. द्वारा अबतक कुल 413 इकाइयों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
  - रू. 4,743.99 करोड़ संभावित पूँजी निवेश सन्निहित।
  - प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 48,876 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना।
  - इनमें कुल स्वीकृत अनुदान रू. 840.81 करोड़ में से अब तक 315 इकाइयों को रू. 510.66 करोड़ अनुदान विमुक्त।
  - 127 इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

- कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 3,845 युवा/ युवतियों को आवासीय प्रशिक्षण हेतु रू. 19.75 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं प्रशिक्षण प्रारंभ है।

मद्य निषेध पर त्वरित एवं सफल कार्यान्वयन हेतु ताड़ के पेड़ के उत्पाद पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं नीरा से बनने वाले उत्पादों के लिए मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना एवं संचालन हेतु कॉम्फेड को जिम्मेवारी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत इस मद में रू. 50.00 करोड़ का उद्व्यय प्राप्त है।

- प्रवासी भारतीय दिवस 2017 में बिहार के स्टॉल का सफल आयोजन बेंगलूरू में दिनांक 07 से 09 जनवरी तक किया गया ।
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत 4 (चार) कलस्टर यथा – कन्हैयागंज झुला कलस्टर, लखीसराय राईस मिल कलस्टर, मेनमेंहसी सीप बटन कलस्टर एवं बथना सीप बटन कलस्टर के "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना हेतु क्रमशः 153.57 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख संतावन हजार), 82.344 लाख (बेरासी लाख चातीस हजार) की राशि विमुक्त की गयी है। चारो कलस्टर में "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनवरी 2017 तक कुल 34 इकाइयों को भूमि आवंटित की गयी है, जिसमें कुल रू. 103.64 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।[23]

निष्कर्ष

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के विकास की बुनियाद कृषि के विकास पर आधारित है। नदियों में जल की प्रचुरता, उर्वर भूमि के अलावा, मेहनती स्वभाव एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य का भाव बिहार के लोगों में भरा हुआ है। अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। इसके विपरीत सीमित संसाधनों के ही आधार पर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि के साथ–साथ उद्योगों का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है।

राज्य में कृषि आधारित उद्योगों, खास कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आहार–श्रृंखला सुविधाओं के सृजन, रोजगार सृजन और निर्यात से आय के जरिए कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की भारी संभावना के चलते 'उदीयमान उद्योग' माना जाता है।

फल और सब्जियों के उत्पादन के लिहाज से बिहार देश का सातवां सबसे बड़ा राज्य है और इस कारण राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर अवसर मौजूद हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं। खाद्य प्रसंस्करण के अलावा पेय, तंबाकू आदि के अंतर्गत ढ़ेर सारे उत्पाद शामिल हैं जिनमें निवल मूल्यवर्धन तथा रोजगार के लिहाज से अच्छी संभावना है। राज्य में चाय और दुग्ध उद्योगों का भी फैलाव शुरू हो गया है। बिहार में अनेक प्रकार के फलों और सब्जियों का बड़ें पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य में 2013–14 में कुल 290 हजार हेक्टेयर जमीन फलों की और 778 हजार हे. जमीन सब्जियों की खेती के अंतर्गत थी। उत्पादन के लिहाज से केला, आम, अमरूद और लीची राज्य के प्रमुख फल हैं। वर्ष 2013–14 में कुल 3,777 हजार टन फलों का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2013–14 में हुए फलों के कुल उत्पादन में केला का 38 प्रतिशत और उसके ठीक बाद आम का 34 प्रतिशत हिस्सा था। कुल फल उत्पादन में अमरूद और लीची का लगभग छः–छः प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2013–14 में राज्य में सब्जियों का कुल उत्पादन 15.629 हजार टन था। सब्जियों में आलू एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका कुल उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत हिस्सा है। अन्य महत्वपूर्ण सब्जियों में प्याज (8 प्रतिशत), टमाटर और फूलगोभी (7–7 प्रतिशत) प्रमुख हैं। राज्य में व्यावसायिक आधार पर फूलों की खेती भी शुरू हो गई है और 2013–14 में 793 हे. जमीन पर कुल 8,831 टन फूलों का उत्पादन हुआ। फूलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गेंदा का है जिसका कुल उत्पादन में 77 प्रतिशत हिस्सा था।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दिसंबर 2013 तक कुल 191 परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिनका कुल परियाजना व्यय 2,606 करोड़ रू. था और उनके लिए 202 करोड़ रू. अनुदान विमुक्त किया गया था। उनमें 15,181 लोगों के लिए रोजगार सृजन अनुमानित है। कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से 111 ने ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया था। सितंबर 2014 तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 328 हो गई और कुल लागत 3,871 करोड़ रू.। इनमें से 180 में व्यावसायिक उत्पादन होने

लगा है। विमुक्त अनुदान बढ़कर 294 करोड़ रू. और अनुमानित रोजगार बढ़कर 21,240 हो गया। खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मुख्यतः तीन प्रकार के हैं – चावल कुटाई, गेहूं पिसाई और मक्का पिसाई। दिसंबर 2013 से सितंबर 2014 के बीच के नौ महीनों के दौरान राज्य में 30 चावल मिल, 6 गेहूं मिल और 11 मक्का मिल इकाइयों का आरम्भ हुआ। राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में यह अच्छा–खासा योगदान है।

सन्दर्भः

1. हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, मंगलवार, 27 सितम्बर 216 : हिन्दुस्तान शताब्दी की ओर परिशिष्ट, पृष्ठ 4
2. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2012–13 के आंकड़े
3. उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट
4. आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, फरवरी 2016, पृष्ठ 138
5. खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट
6. कृषि रोड मैप 2017–2022, बिहार सरकार, अध्याय – 12, खाद्य प्रसंस्करण, पृष्ठ 129–130
7. वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पृष्ठ 1–2